चीन से मुकाबले के लिए यूपी का खिलौना प्लान

इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट खिलौनों के घरेलू उत्पादन पर जोर

अमर उजाला ब्यूरो

पारंपरिक खिलौना क्लस्टरों के साथ यीडा में बनेगा टॉय पार्क

लखनऊ। चीन के खिलौना उद्योग की ताकत को देखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने खिलौना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की रणनीति बनाई है। प्रदेश की खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 में चीन को वैश्विक खिलौना निर्यात में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया गया है। भारत में खासकर इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी चालित खिलौनों में घरेलू निर्माताओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। ऐसे खिलौनों का बड़ा हिस्सा चीन से आयात होता है।

वैश्विक खिलौना उद्योग का आकार वर्ष 2023 में 107.4 अरब डॉलर था, जो वर्ष 2028 तक 137.6 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। चीन के बाद जर्मनी, अमेरिका, चेक गणराज्य और वियतनाम प्रमुख निर्यातक हैं। वर्ष 2022 में भारत का घरेलू खिलौना बाजार करीब 1.5 अरब डॉलर था, जिसके 2028 तक 2.73 अरब डॉलर होने का अनुमान है। पहले भारतीय खिलौना आयात में चीन की हिस्सेदारी करीब 75 प्रतिशत थी। 60 प्रतिशत तक के उच्च आयात शुल्क, बीआईएस प्रमाणन और खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश-2021 के बाद आयात में कमी आई है। इसी अवधि में भारत का खिलौना निर्यात 239 प्रतिशत बढ़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड प्रमुख निर्यात बाजार हैं।

नीति में वाराणसी, झांसी और चित्रकूट के पारंपरिक खिलौनों व लकड़ी के हस्तनिर्मित उत्पादों को प्रदेश की ताकत बताया गया है। झांसी में सॉफ्ट टॉय, वाराणसी में लकड़ी और गोरखपुर में टेराकोटा खिलौनों के पारंपरिक क्लस्टर हैं। इसलिए नीति में इलेक्ट्रॉनिक, एआर-वीआर, स्मार्ट, डिजिटल गेमिंग और एसटीईएम आधारित खिलौनों पर विशेष जोर दिया गया है।

भारतीय निर्माताओं के सामने डिजाइन और नवाचार में निवेश की कमी बड़ी चुनौती है। एमएसएमई इकाइयों में अनुसंधान व विकास, प्रोटोटाइप, सीएडी/सीएएम उपकरण और संबंधित सॉफ्टवेयर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इन कमियों को दूर करने के लिए नीति में क्लस्टर आधारित विकास, डिजाइन सुविधा, परीक्षण और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना और स्फूर्ति योजना के तहत क्लस्टरों के विकास के साथ यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में टॉय पार्क बनाया जाएगा।